ଭାରତର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ମାଓବାଦୀ)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କମିଟି

ओड़िशा राज्य कमेटी

प्रवक्ता- शरतचंद्र मांझी **प्रैस स्टेटमेंट** **दिनांक- 5 नवंबर 2014**

पीएलजीए की 14वीं बरसगांठ पर माओवादी पार्टी का संदेश

2 से 8 दिसंबर तक पीएलजीए की 14वीं बरसगांठ जोरशोर के साथ मनाओ.

नरेंद्र मोदी के झूठे विकास के भाषणों से भूख नहीं मिटती!
विदेशी कंपनियों, जमींदारों व कारपोरेट घरानों से
देश को आजाद करवाने के लिये जनमुक्ति गुरिल्ला सेना में भर्ती हो जाओ !!

प्यारी जनता,

फासीवादी संघ परिवार व्दारा प्रायोजित नरेंद्र मोदी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन, स्विस बैंकों से काला धन वापिस लाने, महंगाई कम करने, विकास व सुशासन के वायदे के साथ सत्ता में आयी. लेकिन पिछले 6 महीनों के शासन ने दिखा दिया है कि भ्रष्टाचार, महंगाई व कुशासन के मामले में पिछली सरकारों से किसी भी मामले में मोदी सरकार कम नहीं है.

पिछले दस सालों से मनमोहन मौन धारण करके विदेशी कंपनियो, दलाल कारपोरेट घरानों व जमींदारों के हित की नीतियां व कानून बनाता रहा तो वहीं नरेंद्र मोदी नाटकीय भाषणबाजी से खुलेआम पूंजीपतियों व विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित में कानून बना रहा है.

मोदी सरकार ने सबसे बड़ा प्रहार देश के मजदूर वर्ग पर किया है. मोदी सरकार ने श्रम कानून, फैक्ट्री कानून व अप्रेंटिस कानून में बदलाव कर के मजदूरों के उन तमाम अधिकारों को छीन लिया है जिन अधिकारों को मजदूरों ने लाखों कुरबानियों देकर अपने संघर्ष के बल पर प्राप्त किया था. इन बदलावों से मजदूरों को अपनी यूनियन बनाना मुश्किल हो गया है. जो देश के संविधान के अनुसार किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है. इतना ही नहीं पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिये अप्रेंटिस कानून में संशोधन कर दिया है. अब मालिक आधे के आसपास अप्रेंटिस मजदूरों को कारखाना में रख सकता है, इस से स्थाई मजदूरों को नौकरी से निकलना आसान हो गया है. इतना ही नहीं अप्रेंटिस मजदूरों का आधा खर्च सरकार देगी वह भी आम जनता से वसूले जाने वाले टेक्सों से. मजदूर विरोधी सरकार होने का इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि मोदी ने जब 'दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव ज्यते' योजना लांच की तो उस समारोह में मजदूरों को नहीं टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे दलाल पूंजीपतियों को बुलाया गया. मजदूर संगठनों ने जहां इस योजना का विरोध किया तो वहीं सभी पूंजीपतियों ने इस का पुरजोर स्वागत व समर्थन किया.

भारत के इतिहास में किसानों व आदिवासियों के सबसे बड़े विस्थापन की तैयारी जोर-शोर के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जारी है. मोदी की जापान, अमेरिका यात्रा, व भारत में चीनी राष्ट्रपति, अमेरीकी रक्षा सचिव की यात्रा इसी का हिस्सा है. मोदी सरकार की योजना है कृषि प्रधान देश को उद्योग प्रधान देश में बदल डालना. इसके पीछे है कारपोरेट घरानों व विदेशी कंपनियों का हित. इसलिये मोदी ने देश में चार औद्योगिक कॉरीडॉरों की घोषणा की है. इसमें शामिल है - 'दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडॉर' (डीएमआईसी), 'अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडॉर', 'चेन्नई-बेंगलोर औद्योगिक कॉरिडॉर' और 'मुम्बई-चेन्नई इकनॉमिक कॉरिडॉर'. इस योजना के तहत बड़ी संख्या में भारी कारखाने, स्पेशल इकनॉमिक जोन, हवाई अड्डे, बंदरगाह, स्मार्ट सिटी, रेल लाईनें, सड़कें आदि बनायी जायेंगी. यह सब आसमान पर नहीं होने वाला. यह सब होगा किसानों व आदिवासियों की जमीनों पर. सीधा सा अर्थ है करोड़ों की संख्या में किसान, आदिवासी और दलित भूमिहीन किसान कहां जायेंगे? सब को उनके पुरखों की जमीन से खदेड़ा जायेगा. खुद की जमीन के मालिक ठेका मजदूरों में बदल जायेंगे. इन योजानओं के लिये मोदी ने अमेरिका, जापान के दौरे किये हैं. चीन का राष्ट्रपति भी भारत आया. सभी से मोदी ने वायदा किया है कि आपके लिये भारत में 'लाल फीताशाही बाधा नहीं बनेगी, आपके लिये लाल कालीन बिछायी जायेगी'. इन देशों की सारी कंपनियां भारत में पूंजीनिवेश करने के लिये शिकारी की तरह तैयार बैठी हैं. इन औद्योगिक कॉरिडॉरों में इन्हीं का पैसा लगना है.

औद्योगिक कॉरिडॉरों में लगने वाले कारखानों के लिये कच्चा माल, प्राकृतिक संशाधनों, खनिज पदार्थों की जरुरत है. इनको चलाने के लिये लोह, कोयला, बॉक्साइट, बिजली आदि चाहिये. इनके लिये निशाना बनाया जायेगा आदिवासी इलाकों को. हमारे ओड़िशा व छत्तीसगढ़ सहित बिहार, झारखंड, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तमाम संघर्षरत इलाके इन संशाधनों से भरपुर है. इसका मतलब यह हुआ कि कारपोरेट व विदेशी कंपनियों के लिये इन इलाकों में खनन करके इनको बरबाद किया जायेगा. इन इलाकों के विनाश पर 'इंडिया का विकास' होगा.

नौजवानों को देश के प्रमुख क्षेत्रों (रक्षा, जीवन बीमा, रेलवे, विनिर्माण, सार्वजनिक उपक्रमों आदि) में एफडीआई (विदेशी प्रत्यक्ष पूंजीनिवेश) के जरिये, 'मेक इन इंडिया' के नाम पर रोजगार के सपने दिखाये जा रहे हैं. जबकि सच्चाई इसके विपरीत

है. जो विदेशी कंपनियां या टाटा. बिरला, रिलायंस समूह आदि की कंपनियां लगातार कर्मचारियों व मजदूरों की छंटनी कर रही हैं, खनन जैसी श्रम आधारित गतिविधियों का भी मशीनीकरण करके मजदूरों की संख्या घटा रही हैं वे कंपनियां कैसे रोजगार का निर्माण करेंगी. ये कंपनियां केवल और केवल रोजगार को घटाने वाली है. न कि बढ़ाने वाली. क्योंकि सब जानते हैं कि एक बड़ी कंपनी लगने से सौ छोटी कंपनियां बंद हो जाती हैं.

'स्वच्छ भारत अभियान' हो या 'प्रधानमंत्री जनधन योजना' सभी पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली हैं. वायु प्रदुषण का जिम्मेदार कौन है, देश का आम नागरिक नहीं. खुले में शोच उतनी बीमारी नहीं फैलती जितनी कारखानों व्दारा हवा व नदियों का पानी प्रदुषित करने से फैलती है. भोपाल गैस कांड के दोषी खुले घूम रहे हैं. जबकि खुले में शोच करने पर मजबूर आम आदमी को मोदी रोज रोडियो पर धमकाता है. क्यों मोदी कारपोरेट घरानों को जिम्मेदार नहीं ठहराता?. स्वच्छ भारत अभियान के तहत होने वाला खर्च अमेरिकी बैंकों, वर्ल्ड बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संस्थानों से कर्ज के रुप में आयेगा. और वह आम नागरिक को ही चुकाना पड़ेगा. जनधन योजना के तहत फ्री में बैंक खाते इसलिये नहीं खोले जा रहे कि गरीबों का भला करना है. नहीं इससे अमीरों का ही भला होगा. खून-पसीने की गरीबों की कमाई को बैंकों में जमा करके पूंजीपतियों के लिये पूंजी जुटायी जायेगी. सरकार गरीबों की जेब में एक भी पैसा नहीं रहने देना चहाती.

दोस्तो, मोदी की नाटकीय भाषणबाजी, हर सप्ताह, दस दिन में रेडियो, दुरदर्शन पर किया जाने वाला उसका ड्रामा एक छलावा मात्र है. उसके तमाशें में तल्लीन होकर, अपनी जेब मत कटवाइये. तमाशाई मोदी की जेबकतरों से साठगांठ है. वह जो सपने दिखा रहा है, वह मायवी हैं, केवल और केवल धोखा. मनमोहन सिंग व पीवी नरसिंगराव व्दारा 1991 में जिन उदारीकरण, निजीकरण व भूमंडलीकरणकी आर्थिक नीतियों को लागू किया गया था, उसका खामियाजा हमारा देश आज बेरोजगारी, गरिबी, विस्थापन, घोर भ्रष्टाचार, महंगाई के रुप में भुगत रहा है. मोदी मनमोहन की नीतियों को और भी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ा रहा है. इसका नतीजा हमें और ज्यादा विस्थापन, गरीबी, असमानता व दमन के रुप में भुगतना पड़ेगा. देश पहले से ज्यादा विदेशी कंपनियों, दलाल पूंजीपतियों का गुलाम हो जायेगा. सरकार ज्यादा क्रुर व फासीवादी तरीके से जनांदोलनों का दमन करेगी.

अगर मोदी के विनाशकारी कदमों को रोकना है, अगर देश को साम्राज्यवाद, सामंतवाद व बड़े पूंजीपतियों से आजाद करवाना है. अगर देश का लोकहितवादी विकास करना है तो केवल और केवल वर्गसंघर्ष ही एक मात्र रास्ता है. बिहार-झारखंड व दंडकारण्य में कार्यरत क्रांतिकारी जनताना सरकारें ही एकमात्र विकल्प हैं. ये क्रांतिकारी जनताना सरकारें देश की जनता के सामने आर्थिक स्वलंबन, सच्चे जनवाद व जनहित में विकास का छोटा ही सही एक नमूना पेश कर रही हैं. यह नमूना शोसक-शासकों की नींद हराम कर रहा है. जल-जंगल-जमीन पर जनता अपना हक कायम कर रही है, लुटेरी सरकार को ध्वस्त कर रही है. यह सब हो रहा है हमारी भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व व पीएलजीए की सुरक्षा में. हमारा क्रांतिकारी आंदोलन पूरे देश में फेलता जा रहा है. छत्तीसगढ़ के धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, ओड़िशा के नुआपाड़ा, बलांगिर, बरगढ़, रायगढ़ा, नवरंगपुर, नयागढ़, बौध, सोनपुर, संबलपुर, सुंदरगढ़, कालाहंडी, कंधमाल की जनता हमारी कमेटी के अंतर्गत एकजुट हो कर संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ रही है.

विदेशी कंपनियों के दलाल रमन सिंग, नवीन पटनायक व मोदी हमारे संघर्ष के विस्तार से घबरा उठे हैं. क्योंकि इस आंदोलन से उनके व्दारा की जाने वाली मनमानी लूट पर रोक लग रही है. इसलिये मोदी एण्ड कंपनी (जनता के खून के प्यासे गृहमंत्री राजनाथ सिंग, वित्तमंत्री अरुण जेटली, विदेशमंत्री सुष्समा स्वराज) सहित नवीन, रमन सरकार हमारे आंदोलन को कुचलने के लिये आपरेशन ग्रीनहंट के तीसरे चरण के तहत हजारों-लाखों पुलिस, अर्धसैनिक बलों को तैनात कर रही है. मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन ग्रीनहंट का तीसरा चरण और तेज होने जा रहा है. अपनी ही जनता के खिलाफ सेना को उतारने की तैयारियां चल रही हैं. जनते के खून के प्यासे गृहमंत्री राजनाथ सिंग ने सभी नक्सल प्रभावित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पुलिस मुखियाओं, अर्ध सैनिक बलों के अधिकारियों व सेना के उच्च अधिकारियों से योजना बनाई है. पहले से तैनात 120 बटालियनों को बढ़ा कर 147 अर्ध सैनिक बलों की बटालियनों को तैनात करने की मंजूरी दी गयी है. सेना प्रत्यक्ष रुप से अभी माओवादी आंदोलन को कुचलने का मार्गदर्शन कर रही है. अब इस फासीवादी बहुमुखी हमले का मुख्य निशाना छत्तीसगढ़ के आदिम जनजाति के निवास माड़ क्षेत्र को बनाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ के लिये केंद्र सरकार ने और दस बटालियनो को तैनात किया है. नगा बटालियनों को मोदी सरकार ने नागालैंड के विपक्ष पुलिस अधिकारियों व नगा जनता के विरोध के बावजुद तैनात किया है.

हमारी ओड़िशा राज्य कमेटी छत्तीसगढ़, ओड़िशा की जनता, किसान-मजदूरों, दुकानदारों, कर्मचारियों, बुद्धिजीवियों व खासकर युवाओं से अपील करती है कि विदेशी कंपनियों, जमींदारों व कारपोरेट घरानों से देश को आजाद करवाने के लिये जनमुक्ति गुरिल्ला सेना में भर्ती हो जाओ! **शहीद भगतसिंग के यह बोल याद रखो कि -अगर कोई सरकार उस देश की जनता को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखती है. तो उस देश के नौजवानों का फर्ज बनता है कि ऐसी सरकार को उखाड़ फैंके!**

- **जनता पर युद्ध 'ऑपरेशन ग्रीनहंट' के तीसरे चरण को हरा ने पीएलजीए में भर्ती हो.**
- **जनता को विस्थापित करने वाले औद्योगिक गलियारों, अभ्यारण्यों, बड़ी परियोजनाओं के खिलाफ संघर्ष करो.**
- **गांव-गांव में क्रांतिकारी जनताना सरकारों का निर्माण करो.**
- **भाकपा (माओवादी) जिंदाबाद.**

प्रवक्ता

शरतचंद्र माझी

ओड़िशा राज्य कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)